

method in which the papers should be reorganised. I am certain that without Government trying to draw their attention to the distortions that might be affected, if Shri Shyamnan-dan Mishra's apprehensions prove to be true, wisdom will prevail.

My hon. friend, Shri Mishra, said that to an extent, he has started suffering already. I think to an extent also some newspapers are doing so to use it as an arm-twist. I hope they will not try to do so.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I am on another issue, the issue which I raised last Friday when the Deputy-Speaker was in the Chair. I expected the hon. Minister of Industrial Development would make a statement today about the NTC's attitude and their decision to increase the price of cloth...

MR. SPEAKER: But there must be some intimation sent to me beforehand. He should not abruptly get up and speak like this.

SHRI VAYALAR RAVI: I expected the Minister but he did not come. Please direct him to come here. (Interruptions). The Minister did not turn up.

MR. SPEAKER: Order, order. We will now resume discussion of the Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill.

12 50 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE
CORPORATION (AMENDMENT)
BILL—Contd.

MR. SPEAKER: We have only 30 minutes left out of the time allotted;

how much time would the Minister like to take?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRIMATI SUSHILA ROHATGI):
15 to 20 minutes.

MR. SPEAKER: Then there is no use asking any other Member to speak. There is no chance for them.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I can cut it down to 10 to 12 minutes.

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS (SHRI RAGHU-
RAMAIAH): There are yet two or
three speakers.

MR. SPEAKER: 12 minutes is all right. I will give three or four minutes each to one or two Members. Now, Shri Daga.

श्री मूलबन्ध डगा (पाली) : अध्यक्ष
में इस बिल का स्वागत करता हूँ। आ एक
बात पर विचार कीजिये। पहले आप की
कोऑपरेटिव सोसायिटीज कोई स्कीम बनाती
है, उस के बाद उस का एग्जामिनेशन होता है
अपेक्स बैंक में, और अपेक्स बैंक को फाइनेंस
करता है ऐग््रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन।
एक स्कीम को बनते हुए कितना समय लगता
है ? पहले स्कीम का एग्जामिनेशन करती
है स्टेट्स की कोऑपरेटिव, उस के बाद अपेक्स
बैंक उस की जांच करता है और उस के बाद
वह ऐग््रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन में
आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब
आप कोई स्माव इतिरोषव स्कीम बनाते हैं
तब उसकी रिफाइनेन्स काले में इतना समय
क्यों लगता है कम से कम आप उस का

[श्री मूलचन्द डारा]

हिस्सा तो बल्लाइये। एक दो साल में स्कीम तैयार होती है, फिर उस को रिफाइनन्स करने में कम से कम एक या दो साल लग जाते हैं। लेकिन उस के बाद भी वह ठीक से पूरी नहीं होती।

मेरे सुनने में आया है कि इरिगेशन स्कीम्स कई कई जगहों पर बनती हैं। इरिगेशन स्कीम्स इरिगेशन डिपार्टमेंट भी चलाता है, कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट्स भी चलाती हैं, प्रो० शेर मिह यहा चैंटे हुए हैं, उन का डिपार्टमेंट भी चलाता है, कृष प्रोग्राम भी चलते हैं। मैं जानना चाहता हू कि यह ओवरलैपिंग क्यों है। इरिगेशन स्कीम्स का चलाने के लिए आप का कम्प्यूनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बर्क करता है, स्माल इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बर्क करता है ग्रुप के यहा कृष प्रोग्राम्स भी चलते हैं। फिर् बैकम का नेशनल इन्वैज्शन होने के बाद आदर्श डाइरेक्ट लोन के लिये बहा जा सकता है। मैं आप से जानना चाहता हू कि बैकस का नेशनल इन्वैज्शन होने के बाद इम बिन की क्या आवश्यकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप का क्या तरीका है।

इन विधेयक में एक बड़ा सुझाव यह है कि आज से उन लोगों को जो स्माल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, लोन मिलेगा। इस सम्बन्ध में सब से बड़ा डिफिक्ट यह है कि जो रिफाइनन्स करने वाले हैं वह ऐग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते। स्कीम तो सारी ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है और पैसा देने वाले आप हैं। आखिर सारा पैसा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों न दे ?

इस बिज के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हू। मैं जानना चाहता हू कि क्या देश के अन्दर एक भी सोसायटी लेवर्स क्वी बनाई गई और क्या उन को कर्जा मिला है। मैं कहता हू

Land has been been allotted. Now, can that man get a loan or not? The

land was allotted and the patta has been issued. Even then, can that landless labourer get help from any source or not?

जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उन का कोई रिफाइनन्स नहीं होता है। उन की किसी कोऑपरेटिव का बनने के बाद रिजस्ट्रेशन नहीं हुआ है। देश के अन्दर जितनी कोऑपरेटिव सोसायटीज हैं उन का सारा काम आफिसों के तरीके पर होता है। जब तक उन में आफिसों का अलिम बना हुआ है और वह हटता नहीं है तब तक काम नहीं चल सकता। अगर कोई भी छोटी सी गलती कर दे, कोऑपरेटिव सोसायटी में कुछ गड़बड़ हा जाय ता सारा आफिस उस को ले कर बैठ जाता है। मेरे खयाल में तो एलेक्शन भी कोऑपरेटिव्स के टाइम पर नहीं होते। आप यहा पर कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना चाहते हैं, उन के जर्ग्ये लोन भी देना चाहते हैं। ऐसी हालत में पहला काम यह होना चाहिये कि कोऑपरेटिव्स के एलेक्शन इन्फ्लुएन्स की तरह पर हाने चाहिये और उन की मशीनरी अलग हॉनों चाहिये नहीं तो आप का काम नहीं चल सकता।

दूसरी बात यह है कि जो आप के आफिसर्स हैं उन का इन्फ्लुएन्स नहीं होना चाहिये। हर कोऑपरेटिव सोसायटी के बाहर आप का इन्स्पेक्टर बैठा हुआ है जो उन को खा जाने के लिये मौजूद है। 100 गलतिया करते रहो और उन को खिलाते रहे तो कोई बान नहीं है, लेकिन अगर छोटी सी गलती हो जाय और कोऑपरेटिव पैसा न दे तो उस का काम नहीं चल सकता। जितने भी कोऑपरेटिव बैकस हैं उन के साथ आफिसर्स का जो सम्बन्ध है वह टूट जाना चाहिये। जितने ही कम आफिसर्स हो उतना ही अच्छा है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसायटीज बर्क कर रही हैं उन के साथ आप के आफिसर्स लगे हैं, कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर, डिप्टी रिजस्ट्रार, असिस्टेंट रिजस्ट्रार, वह स्कीम्स का एग्जामिनेशन करते हैं। कृषी आप गावों के अन्दर जा कर इन बातों को देखिये। जो

आप के लैंडलेस लेबरर्स को पैसा देने की स्कीम है उन में बहुत ज्यादा प्रोविसींग है ।

आजादी के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर स्माल और माजिनल फार्मर्स बहुत हो गये । गावों के अन्दर कुछ लोगों के हाथ में दौलत आ गई । गरीब गरीब ही रहे और मालदार और मालदार बन गये । आप किसी भी गाव में चले जायें, जिन्होंने किसी तरकीब से पैसा हड़प लिया उन्होंने हड़प लिया और जो गरीब है वह और गरीब बन गया । पच्चीस साल के बाद भी जो पहले आखिरी पक्ति में खड़ा हुआ था वह आज भी आखिरी पक्ति में खड़ा हुआ है ।

मैं इस अमेन्डमेंट का स्वागत करता हूँ, लेकिन इस रिफाइनेंस कारपोरेशन में एक बात है । जो इस मंडरेटरी लागू है उन में हमारे रिप्रेजेन्टेटिव कितने हैं ? नारा की सारी मशीनरी उप के अन्दर गवर्नमेंट को है । हम लोगों की आवाज उस में नहीं उठती है । वहाँ पर सब एम्प्लायीज गवर्नमेंट के हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि यारिंग आप पावर का विकेंद्रिकरण करना चाहते हैं या सेटलाइजेशन करना चाहते हैं ? किसी भी स्कीम के लिये आदमी को आप के पाम आने की जरूरत क्या है ? गावों के अन्दर जो स्कीम आप की है उन के लिये स्टेट लेवल पर लोन मिल जाना चाहिए क्योंकि आप के पाम आने में तो दो दों चीजें लग जाते हैं । ऐसी स्थिति में इस बिल का परपज हल नहीं होता ।

SHRI RANABHADUR SINGH (Sidhi): I welcome this amendment. My only submission is that the pace at which the ARC is being tailored to the needs of the rural credit is a bit slow. Last time an amendment was passed in this House on July 31, 1971. It has taken almost two years for the next move to be made. I think that at this rate of ARC will re-

main hanging in the air and it will take a very long time for it to be meaningful in meetings the needs of rural credit. I suggest that apart from this amendment, Government take very urgent steps to bring about procedural simplification in their ways of giving loans to schemes in the rural areas.

13 hrs.

One of the things I would like to mention in this context is that one scheme was sanctioned by the ARC for electrification of pumps in the rural areas and digging of wells. Fortunately, for an area which fell in that unit there was a perennial stream running through that village. So, the villagers wanted to use electric pump without digging the well. It was a mortification for the villagers when they were told that since the ARC had sanctioned the scheme for wells and pumps, they would not give any loan only for pumps, in spite of the fact that water was available in the stream. I would say that cases like this are proof enough that the ARC is not in touch with the rural credit needs, and that is what I mean when I say that procedural simplifications are called for.

I would also plead that the consultancy services that have been set up by the ARC at present are limited to the eastern sector of the country. They should be more widely spread. It is my request that a consultancy service centre must be opened in Bhopal to cater to the widely divergent needs of a large State like Madhya Pradesh, specifically because out of the Rs. 30.62 crores that have been funded by the ARC so far, Madhya Pradesh has received only Rs. 91 lakhs.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I would like to thank all the hon. Members who have participated in this debate. I think, by and large, this Bill has

been unanimously supported. I welcome the suggestions that have been made.

MR. SPEAKER: She may continue her speech after lunch. The House stands adjourned till 2 O'Clock.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Sushila Rohatgi to continue her speech....

श्री सद्दु लिवये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ग्रहम और जरूरी सवाल की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री श्री मंत्री महोदय ने लोको स्ट्राइक के बारे में बयान दिया है। लोको की स्ट्राइक समाप्त हुई, उस पर हम सब लोगों को खुशी हुई है। लेकिन राजस्थान में एक महीने से अधिक समय से हड़ताल चल रही है। टीयरगैम का हमला हो रहा है और लाठियाँ चल रही हैं। सैकड़ों लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया आप कह सकते हैं कि यह राज्य का मामला है। लेकिन आखिर सरकारी कर्मचारी ग्राज हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं ? जरूरत की चीजों का अभाव है, दाम आसमान को छू रहे हैं, जिस के लिए केन्द्र जिम्मेदार है। यहाँ के गृह मंत्री, श्री राम निवास मिश्रा, का राजस्थान से सम्बन्ध है। क्या वह राजस्थान को सरकार और वहाँ के सरकारी कर्मचारियों में बीच-बचाव कर के इस हड़ताल को समाप्त कराने का प्रयास करेंगे ? संसदीय-कार्य मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। वह हमारी भावनाओं को श्री मिश्रा तक पहुंचा दें कि वह

1453 L.S.

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने, और कोई समझौता कराने का प्रयास करें।

श्री कृष्ण चन्द पांडे (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वजिल में पहले भयंकर सूखा पड़ा था और अब वहाँ भयंकर बाढ़ आ गई है। हम चाहते हैं कि इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या बहस को स्वीकार किया जाये, ताकि हम लोग अपनी समस्याओं को यहाँ पर रख सकें। उत्तर प्रदेश में भाज राष्ट्रपति शासन है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये।

14.07 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL—Contd.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think, I will start by thanking all the hon. members for their valuable suggestions. It is only natural that, in the course of the discussion of this Bill, the functions, the operations, the objectives and the entire working of the various financial institutions should have been discussed, whether they are directly or indirectly concerned with refinance.

So far as this particular Amendment Bill is concerned, it relates to only refinancing and has the limited objective of augmenting the resources which are available to the financial institutions with a special eye on encouraging, and on alleviating the miseries of, those people who are small farmers, who are agricultural labourers and those who have no land whatsoever. All the hon. members, irrespective of their party affiliations, have appreciated this objective.

[Shrimati Sushila Rohatgi]

I would only like to allay the fears and apprehensions expressed by Shri Bhogendra Jha, who is not present here now. He had some apprehension that this might be utilised in a manner which would be detrimental to the very objective. I would like to assure him that that is not the purpose. In fact, the various suggestions that have been made by the various speakers would be taken into consideration, and where there are difficulties, where there are obstacles, where there are impediments in the way of proper operation, I would assure them that we shall look into the matter.

Now I wish to draw the attention of the hon. members to the work done by the ARC. It is true that, in the first four years, the work was not as good as it should have been. Anything in the offing takes a little time to walk on its own feet. But since 1958 the working of the ARC has been appreciable. I am happy to tell the members—and they are aware of this fact—that at present 888 schemes have been sanctioned by the ARC and the financial outlay comes to Rs. 524 crores. And they are at various stages. But I would like to clarify one point. It was asked by an hon. Member as to why the disbursements are slow and why the money is lying unutilised. There is no question of money lying unutilised because the money is sanctioned for the entire project, and it is phased out in various stages. After a certain phase of the project has been completed and if more money is needed for refinancing, the requisite finance is given. Therefore, there is no question of unutilisation and no project is held up because of finance whatsoever, because the sanction is for the entire project as a whole.

The present picture is: out of 888 schemes—I would also like to give the break-up for the information of the hon. Members—about 60 per cent of these schemes are concerning

minor irrigation which are of extreme importance to the country as a whole.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): Would you just lay on the Table the various schemes and the stages at which they are now for the information of the hon. Members so that we may be enlightened?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I would be very happy to do that. Apart from that, if I may take your indulgence for a minute, I would draw your attention that out of 888 schemes, a major part, nearly 60 per cent has gone to minor irrigation. They account for 536 schemes. Land development, tractors and power-tillers, soil conservation, plantation, poultry farming, fisheries, dairy development and for construction of godowns, silos, marketing yards and sheds. These are the major schemes. I have got the exact number and the amount utilised and I would be very happy to pass it on to the members.

Some members have mentioned that there is a lot of delay for according sanction. One hon. Member mentioned that it takes years and takes a long time for any scheme to be really sanctioned and, therefore, this delay factor must be eliminated. I would like to clarify this point. There is no question of delay. In the beginning there was some delay, but now, the refinancing part with which this Bill is concerned, does not take any time at all, for at the time of the formulation of the scheme itself, all these agencies—the State Government, the Co-operative Bank, the commercial bank and the ARC discuss it and they work as a team and once any particular institution which is financing or the Agricultural Refinance Corporation accepts the scheme, whether it be the co-operative bank or the commercial bank, it goes ahead with the work of financing these schemes and the refinance is done even at a later stage. It is not because of the ARC that any work

on these particular schemes is held up and, therefore, the delay factor is not the responsibility of ARC. Even otherwise, there is scope for improvement and certainly we welcome the suggestions given by the hon. Members.

I am very happy to state that the Consultancy Service which has been instituted with its head office at Lucknow has done good work and in the immediate future we are starting a consultancy office at Calcutta also. So far 76 schemes have been finalised through this consultancy service. I have also got the break-up here. They are in various States. In Assam we have 6 schemes, in Bihar 6, Meghalaya 7, Orissa 14, West Bengal 17 and West U.P. 26. These are the schemes which have been really sponsored through the consultancy service which has done so much in the course of less than two years. Therefore, another office is to be set up at Calcutta.

Certain allegation was, however, made by an hon. Member from Tamil Nadu. He said that there is a discrimination and he asked why a consultancy centre was not set up in Tamil Nadu. I may tell him that no work in Tamil Nadu has suffered because of it and Tamil Nadu is able to look after itself very well. It is only the Eastern districts and North-eastern districts because of lack of infra-structure and other conditions are not able to do very well. Therefore, it is giving a momentum for their development.

I shall quote the figures about the Tamil Nadu to clear up if there is any lack of coordination. A point has been made invariably by all the Members and do feel that this is a relevant point and there is, to some extent, regional disparity which still exists. I feel that the regional disparity still exists in the places from where you and many of the Members come from. All of them realise that this regional disparity must be removed. If not immediately, they

must at least be mitigated at the earliest. I am glad to say that the Government being aware of this, especially, the A.R.C. being aware of this, to-day, has taken certain corrective steps in this direction. The steps that are taken in this regard are: special meetings had been convened or sponsored by the A.R.C. between the Agriculture Ministry—they are convened at the initiative by the Agriculture Ministry—and the State Governments. They have involved the State Governments—representatives—and various financing agencies and they have reviewed the various difficulties and impediments that stand in the way. We hope that they will try to prevent or remove the regional disparities. On the basis of certain suggestions that have been made here, the Finance Minister himself had called a meeting of ten States and their Agricultural Production Commissioners and had talks with them and other States' representatives. On the basis of these meetings, a number of steps had been taken. As a consequence, it has been decided that where the cooperative societies are weak, they must be strengthened; there must be greater coordination between the various financial institutions. Also there must be greater coordination between the State Governments and various project authorities and various financial institutions. The recommendations of the Talwar Committee would be implemented as early as possible.

Apart from that, now, we have regional offices in almost all the States. In Gauhati also, a centre has been opened. Therefore, almost all these States are really covered; their working is looked after by the regional officers. Apart from that, some State Governments have special cells also which are looking after specifically the schemes to be sponsored for A.R.C. Some of the schemes fall under the S.F.D.A.—Small Farmers Development Agencies. Almost all State Governments are trying to sponsor schemes for small farmers—

[Shrimati Sushila Rohatgi]

marginal farmers—who are the vulnerable weaker sections. A.R.C. even gives them 100 per cent re-financing for these vulnerable sections of the society which will indeed be a step in that direction. Members would like to have the break-up of the various schemes in various States. I would like to point out here that because of various steps that had been taken, there has been progress made by the S.F.D.A. in regard to small and marginal farmers' requirements. The break-up as on 30th June, 1968 was as follows:

In Assam, they were four. Let me first tell you that the total number of schemes at the end of January, 1968 was 128 in all the States. The A.R.C.'s schemes have been increased from 128 to 888 and their outlay has also been increased to Rs. 524 crores. About the details of the small and marginal farmers, the position as it stands now is as follows:—

Number of Schemes

As on 31-5-1973

Andhra Pradesh	3
Haryana	1
Himachal Pradesh	1

The total number comes to 36. Financial assistance is of the order of Rs. 39.71 crores—this is for the small and marginal farmers. I am not saying that this is precisely the reason why the Bill is coming up. That is because the banks and the cooperatives have really taken the initiative on this. It is because of them that so many schemes have come up. After all, the A.R.C. have also play their role in the matter of preparation of techno-feasibility report for the schemes. In this context, we would like much more resources to be placed at the disposal of the small farmers and the marginal farmers.

At present, you aware there is a certain legal difficulty according to which financing cannot be done without mortgage of land or government guarantee. That is a delaying process and acts as a bottleneck. If the Bill is passed, this difficulty will be

removed and it will permit of much greater resources being available for refinancing, resources which would be placed at the co-operative and commercial banks.

As for the future, we have a great future. The basic approach of the ARC is to give the maximum possible support subject to financial constraint to the small farmers to the people who are really needy, and also to remove regional disparities. For this a number of suggestions have been made. Government are considering all these. I will not take the time of the House on this. An interim report has also been presented by National Commission on Agriculture. Government would study all these facts. I am happy to say that with the help of IDA a number of schemes have been taken up in various States. Because of the good work done by ARC today, the IDA is also helping them and the fact that IDA should be prepared to sanction a direct line of credit speaks highly of the work of the ARC.

With these words, I thank hon. members and hope they will pass the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, be taken into consideration”.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up clause by clause consideration.

There are no amendments. The question is:

“That clauses 2 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clauses 2 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI.
I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR DEPUTY-SPEAKER Motion moved.

"That the Bill be passed"

श्री मधु लिमये (बाका) उपाध्यक्ष महादय, इस बिल के उद्देश्य ने मान्यता है। लेकिन गवाल यह है कि जो मशोधन हमारे सामने आया है उस का इस्तेमाल कैसे होगा? यह जो रीफाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन है, यह तो किसी भी योजना पर अमल करने वाला सभ्यता है दूसरी है, फायरिंग वैंक है, लैंड डवलप-मेंट वैंक है, गैज्यूड और फार्मिगल वैंक है, इन सबका के द्वारा योजनाओं पर अमल होता है और मैं यह कहने के लिये बाध्य हूँ कि राष्ट्रीयकरण के बाद इन सभ्यताओं के दृष्टिकोण में कोई बुनियादी फर्क नहीं आया है। मैं आप ही की इस किताब से कुछ वाक्यों को उद्धृत करना चाहता हूँ—सारी योजनाओं का आधार है—सिक्योरिटी, इस छोटी सी पुस्तिका में जो आप की किताब है—इहा गया है—

*Agricultural Refinance Corporation :
Functions and Working*

"Schemes sanctioned in respect of scheduled commercial banks: the securities to be sub-mortgaged/hypothecated by the ultimate borrower in favour of the financing bank and refinance, provided to the extent of 50 per cent of the value of the securities".

आगे दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है—

"The cultivators to be financed under the schemes should be those

who have mortgageable or alienable rights over their holdings which are proposed to be mortgaged to the financing institutions. Further, the cultivators should preferably contribute a part of the funds required from their own resources to the extent possible with a view to ensuring that they take keen interest in the schemes evolved for their benefit"

अब उपाध्यक्ष महादय संघाल परगना, जिस का एक क्षेत्र मर समर्दाय क्षेत्र के नीचे आता है उस में— स्थिति जो की जगती के लिये, जगती जगती, — जगती या कानून अपनी जमीन का आदिवासी को देने की छूट नहीं देता है, ऐसी स्थिति में उन के पास "एनिलियेबिल जमीन" नहीं है

श्री जगदीश नारायण मडल (गोहा) संघाल परगने में खानी आदिवासी ही नहीं, गैर-आदिवासी भी जमीन भी बंधक नहीं होती है। वैंको से उन को कोई लाभ नहीं है।

श्री मधु लिमये इस समय जो संघाल परगने का कानून है, मैं उस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्डोने एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिये बिल रखा है। आदिवासी इस भूमि कानून के तहत अपनी जमीन नहीं बेच सकता, इस लिये उन को इस का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि "एनिलियेबिल लैंड" उन के पास नहीं है, कानून ने गिरवी नहीं रख सकते हैं, न सम्पत्ति है जो गिरवी रख सके, न जमीन है जो गिरवी रख सके—ऐसी स्थिति में संघाल परगने के जो गरीब किसान हैं, उन की समस्याओं पर भी विचार होना चाहिये।

दूसरी बात—यह जो सिक्योरिटी वाली बात है, मेरी समझ में नहीं आता, जब छोटे किसानों का खयाल आता है जो वे बैंक वाले, खास कर कार्मिथियल बैंक वाले पचास किस्म

[श्री मधु लियमय]

के अग्रगं डालते हैं और लैंड डेवलपमेंट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जहाँ तक सम्बन्ध है, उस पर बड़े जमींदार और बड़े काश्तकार हावी है, इसलिए छोटे किसानों को इन सारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता ।

लेकिन जो कामर्शियल बैंक है, जिन का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उन का पूँजीपतियों के साथ व्यवहार कैसा है ? वास्तव में इन व्यापारिक बैंकों और पूँजीपतियों के घरानों का जो गहरा रिश्ता था, जिसके चलने बैंकों के माधनों का इस्तेमाल पूँजीपति अपनी सम्पत्ति को और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिये करता था, उसमें मुक्ति दिलाने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इन राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिये, इस सदन में हमने कई सशोधन दिये थे लेकिन एक सशोधन के अलावा दूसरा कोई सशोधन नहीं माना गया । कर्मचारियों के प्रतिनिधि लेने की बात है, काश्तकारों के प्रतिनिधि लेने की बात है लेकिन हो क्या रहा है ? सुशीला जी जिम इलाके में आती है,—उस कानपुर की एक घटना के बारे में बतलाना चाहता हूँ—कानपुर, नया गज में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है । आप को आश्चर्य होगा, यह शाखा जे० के० ग्रुप की एक शाखा के रूप में काम करती है, यह राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है, यह जे०के० ग्रुप की शाखा है और आज जे०के० ग्रुप में इनकी उदरभूना आ गई है कि नया गज बैंक के मैनेजर को वह पत्र लिखते हैं—मैं एक पत्र का नमूना लाया हूँ और आप की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ । आप पूछेंगे कि रीफाइनेन्सिय से इस का क्या सम्बन्ध है ? मैं दो दुनियाओं की तस्वीर आप के सामने खींचना चाहता हूँ—एक ओर संभाल परमै के आदिवासी और छोटे किसान हैं, जिनके पास धरती के लिये जमीन नहीं है, जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, उन की

क्या हालत है और दूसरी तरफ़ इन बड़े लोगों की क्या हालत है । यह पत्र 9 मई, 1973 को जे०के० रेयोन में पंजाब नेशनल बैंक, नया गज शाखा को लिखा है—

“Dear Sir,

Consignment of 6,672, bales of wood pulp by SS Viswabhakti

We have to inform you that the above consignment has been imported by us and the ship is touching Calcutta port on or about the 15th instant. We require a sum of Rs 11,20,000 to clear the said consignment from the port. You are requested to kindly take the above 6,672 bales of wood pulp under pledge with you and issue us a bank draft for Rs 11,20,000 in favour of Messrs Calcutta Shipping Bureau payable at your Calcutta counterpart and your charge in this connection may please be debited to our account with you. For your information, we may add here that the cost of 6,672 bales of wood pulp comes to Rs 44,03,520, that is, at Rs 660 per bale. The BP comes to Rs 32,02,640. Yours faithfully”
“Please issue draft”

उसके नीचे मैनेजर का नोट है—

इसमें खूबी क्या है ? जो माल आ रहा है, जिसको ये गिरवी रखना चाहते हैं, वह समुद्र पर है, विषय-भक्ति जहाज समुद्र पर है, वह माल अभी कलकत्ता नहीं पहुँचा है, कानपुर आते-आते दो महीने लगने वाले हैं, माल आयेगा या नहीं आयेगा, इसका पता नहीं है, हो सकता है विषय-भक्ति डूब जाय, लेकिन जो माल इनके कब्जे में नहीं आया और इनके गोडाउन में नहीं पहुँचा है, दो महीने के बाद पहुँचेगा, उसके लिये वे लोग 11 लाख 20 हजार रुपये—दो-तीन हजार रुपये नहीं—माँगते हैं । और मैनेजर लिख देता है इनको दे दिया जाये । कितने दिनों में बिलयर होता है ?

चार दिनों में ड्राफ्ट मजूर हो जाता है। सोचने की बात है कि जे०के० के लिए जो लिमिट दी गई है उस एकाउन्ट में क्या उसको

SHRI K P UNNIKRISHNAN (BADAGARA): Sometimes the banks are also very efficient

श्री मधु लियने इसीलिए आप देख रहे हैं कि चार दिन में मजूर हो जाता है। आश्चर्य की बात है इस एकाउन्ट के लिए जो लिमिट निर्धारित की गई थी उसको भी एकमोड करते हैं जे०के० नेयान वाले। और क्या क्या करते हैं उम के बारे में बिल मन्त्री का मैंने पत्र भी लिखा है। ता चकि मैनेजर की इसके ऊपर नाटिंग है इसलिए आपकी आज्ञा से यह वागव्र सभा-पटल पर मैं रखना* चाहता हूँ। इसकी आज्ञा आप इजाजत दें ताकि अखबार वाले खूब अच्छी तरह से उसका छाप सकें।

इसमें साथ साथ दो बानों को मैं और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कार्ड इर्रेलेवेन्ट बात नहीं कही है। मैंने कानून को नाड कर, जो माल ममुन्दर में हो, जा उनके गोडाउन में आया तक नहीं है, कोई बिल आफ नेडिंग नहीं है, उसके अगेन्स्ट चार चार दिन में 11 लाख 20 हजार रुपया मिल जाता है। ता अभी आपने जो सशोधन रखा है क्या उसको तहत चार दिनों में गरीब किसानों, आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों के जो लोन के लिए आवेदन-पत्र आयेगे उनको मजूर करवाने की कोई योजना होगी? क्या शेड्युल्ड बैंक्स, स्टेट कोओपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेन्ट बैंक्स को जरा सहानु-भूतिपूर्वक दृष्टि से उन आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए कहा जायेगा? यदि नहीं, तो मैं कहूँगा कि आपका यह सशोधन घोखाघड़ी है जैसे कि 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण एक बड़ा घोखा साधारण जनता के साथ हुआ। यदि आपके मेरे सभी

सशोधनों को माना होता और जो—घरत लोग हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की होती तो मेरा खयाल है आज यह नोबत नहीं आती।

MR DEPUTY-SPEAKER: You may give the paper to me I have not given permission for laying it

श्रीमति सुशीला रोहतासी माम्यवर, मैं माननीय सदस्य की बड़ी आभा हूँ कि इस प्रकार की किसी घटना की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके सम्बन्ध में मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं है परन्तु आपके माध्यम से मैं इतना विश्वास दिलाऊँगी कि यह जा चात्र है, जैसा उन्होंने कहा है इस आरोप को देखा जायेगा, इसकी जाच की जायेगी और जो भा होगा वह माननीय सदस्य को अवश्य सूचित कर दिया जायेगा। चाहे कानपुर का नयागज हाँ चाहे गाढ़ाघरत बैंक हाँ या कोई भी बैंक हाँ उनमें कोई भी अन्तर नहीं है। एव ही नीति है और उमी के आधार पर, उन्ही डायरेक्टिन्स के आधार पर जितनी देश का राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको काम करना है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि चार दिन में इन चीजों को हटाकर कार्य पूरा किया है

श्री मधु लियने कानून को तोड़कर किया है।

श्रीमती सुशीला रोहतासी आज उन कानूनों का परिवर्तन करके हम किसानों को मदद देना चाहते हैं। यह बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शुरू में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस वक्त आपके मन में जो मशय होगा उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। इत बैंकों के माध्यम से जितना रुपया दिया जा रहा है...

श्री मन्त्री किराणू शर्मा: लैंड मांटगेज बैंक की कार्यवाही और प्रोत्साहन को जितना

*The Speaker not having subsequently received the paper, the same was not treated as laid on the Table.

[श्री नवल किशोर वर्मा]

नहीं बदलगे तबतक कर्जा नहीं मिल सकता है ।

श्रीमति सुशीला रोहतगी हमने पहले भी ध्यान में रखा था और आगे भी रखेंगे । राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वह आपके विचार में सफल नहीं हो रहे हैं लेकिन हमारे विचार में सफल रहे हैं । यह बात अवश्य है कि उनमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है । (ध्यान)

मैं मन्त्रिमंशे जी में कहना चाहती हूँ कि मेने बड़ा आनंद से आपकी बात सुनी है । मेने कहा है जबतक इसका खंडन नहीं होता, जब तक मुझे इसकी जानकारी न हो तबतक मैं कुछ करने की योजना में नहीं हूँ । अवश्य इस बात की जानकारी होनी चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a lady appeals for sweetness, you must respond.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Thank you, Sir. I am sure he will respond.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है उसपर मैं विशेष बल देना चाहती हूँ । अभी तक जो दिक्कत रही है सेक्योरिटी की, मार्गेंज की उसको हटाने के लिए यह बिल आया है । आपकी और हमारी राय में किसी तरह की भिन्नता नहीं है, जो आपके विचार है वही हमारे विचार है । इसलिए जो आपने कहा है, अगर आज वह हो जाता है जो सेक्योरिटी की आवश्यकता होती है जिससे लीगल कठिनाइया उत्पन्न होती है उनका आसानी से समाधान कर सकेंगे और जो गरीब हैं चाहे वह संघर्ष हों या आदिवासी हों, गरीब को कोई धनगत से बंधन नहीं होती, वह

गरीब चाहे किसी भी प्रवेश का हों, उनके पास जमीन है या नहीं या जो लैंडलेस नेचरर है उसको सारी रिफाइनन्स की फेसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिए । इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ । मार्गेंज को हटाने और सेक्योरिटी को रिन्वेन्स, लिक्विडाइज करने के लिए यह बिल आया है ।

दूसरी सारी बात जो है उनके सम्बन्ध में पहले ही चर्चा हो चुका है इसलिए मैं मन्त्रिणी हूँ इस बिल का पूरी तरह से जोरदार समर्थन दूँगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted.

14 35 hrs

SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL), 1973-74

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up Supplementary Demands for Grants (General).

DEMANDS No. 11—FOREIGN TRADES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,28,00,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 74,00,00,000 on Capital Account be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1973, in respect of 'Foreign Trades'."